

पुस्तकालय

(1)
3182
12/3/12



असंशोधित

28 FEB 2012

बिहार विधान-सभा दादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

—
(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शास्त्रा
गै० स० प्र० स० १०५ तिथि ०७/३/१२

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी ।

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं है सरकार के अधीन । राघोपुर दियारा का इलाका है, वहां सरकारी भवन की कमी है। इसके चलते रेफरल अस्पताल में तत्काल संचालित है बाल विकास परियोजना का कार्यालय तो मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहता हूँ कि वे एक समय सीमा तय करें कि इसे अगले वित्तीय वर्ष में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा दें ।

श्री परवीन अमानुल्लाह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए राशि आती है नवार्ड से, आर०आई०डी०एफ० से इसकी राशि आती है तो उनसे हमलोगों को बात करना पड़ेगा इसके निर्माण के लिए। इसके लिए वे सहमत हैं या नहीं कि सी०डी०पी०ओ० का कार्यालय कंसट्रक्ट हो लेकिन हमलोग जरूर उनसे बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि काम हो सके ।

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जमीन उपलब्ध है तो प्राथमिकता दिया जाय राघोपुर के लिए और इसको अगले वित्तीय वर्ष में बनवा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने इसको गंभीरता से लिया है और इसको प्राथमिकता में अगले वर्ष लेंगी ।

श्री सतीश कुमार : जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं०-२३४(श्री अरुण शंकर प्रसाद, स०वि०स०)

श्री प्रशान्त कुमार शाही, मंत्री : खंड-१ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

संख्या के आंकड़ा का कोई निश्चित डाटा उपलब्ध नहीं है ।

खंड-२ उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुतः राज्य में सम्प्रति १५ विश्वविद्यालय संचालित हैं। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैय्या कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

खंड-३ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खंड-४ राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों में वर्तमान जो विश्वविद्यालय हैं, उनके पुनर्गठन की आवश्यकता है। जिसके संबंध में सरकार भविष्य में कार्रवाई करने की इच्छा रखती है ।

श्री अरुण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहां बिहार के छात्र पलायन करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं तो जब हम बिहार का विकास चाहते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो जहां आन्ध्रप्रदेश में ४२ विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में ४७ हैं, कर्नाटक में ४० हैं तो क्या इस तर्ज पर बिहार में आबादी के अनुपात में विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं?

श्री प्रशान्त कुमार शाही, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ। राज्य में और विश्वविद्यालय की आवश्यकता है और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि आवश्यतानुसार किया जायेगा महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं०-२३४ का पुरक

श्री अरुण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो गया, माध्यमिक शिक्षा सुधार की स्थिति में है तो अब उच्च शिक्षा में सुधार के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, इसलिए आप कबतक कितने विश्वविद्यालय का प्रारूप तैयार किये हैं इस बिहारके अन्दर हमें खोलना है, उसकी प्रक्रिया पर कोई कार्रवाई हो रही है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही साकारात्मक जबाब दिया है आपको । सरकार प्रयत्नशील है और जरूरत के अनुसार उस दिशा में कार्रवाई भी कर रही है और आगे भी करेगी । अब आप बैठिए ।

डॉ० अच्युतानंद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने साकारात्मक जबाब दिया है तो बिहार से २.५ लाख छात्र प्रत्येक साल देश के दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और एम०बी०ए० के भी छात्र हैं । एक छात्र पर करीब पर ईयर दो लाख रूपया कम-से-कम खर्च है साधारण छात्र को और इस हिसाब से जब साधारण छात्र यदि २.५ लाख रूपया जाता है तो ५ करोड़ रूपया बिहार का यदि पर ईयर होता है और मेडिकल, इंजीनियरिंग और एम०बी०ए० एवं अन्य टेक्निकल के छात्र जाते हैं तो उसका कैपिटेशन फी २५-२५ लाख रूपया लिया जाता है, इस प्रकार से ५० लाख से लेकर करोड़ों रूपया, अरबों रूपया बिहार से पलायन हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस बिहार की जो आर्थिक क्षति हो रही है प्रत्येक साल, उसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय या मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का यथाशीघ्र विचार करती है पी०पी०पी०मोड पर ।

अध्यक्ष : यह तो पहले ही माननीय मंत्री जी ने जबाब दे दिया ।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितने विश्वविद्यालय हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही है तो कितने पद सृजित हैं, वह सृजित पद में पूरे पद पर कितने पद रिक्त हैं और कितने पद पर लोग पदस्थापित हैं, इसके बारे में हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : यह अलग से क्वेश्चन आप रखिए ।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह : इसी प्रश्न में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में है...

अध्यक्ष : अलग से प्रश्न लाइए ।

तारांकित प्रश्न सं०-२३५, मा० सदस्य श्री प्रदीप कुमार

श्री गौतम सिंह, मंत्री : महोदय, खंड-क- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला के हिसुआ अंचल में चिंहित ५.७७ एकड़ भूमि को हस्तान्तरित किये जाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय सहमति प्रदान की जा चुकी है । भूमि हस्तान्तरित होने के पश्चात पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा सकेगी ।